हिंदी दैनिक

न्यूज़ वायरस

वर्ष : 11 अंक : 01 | देहरादून, बुधवार, 15 जून, 2022 | मूल्य : एक रुपया | पृष्ठ : 08

10 साल दैनिक न्यूज़ वायरस के स्वर्णिम सफर के साथ

मो. सलीम सैफी, समूह संपादक

आशीष तिवारी, कार्यकारी संपादक

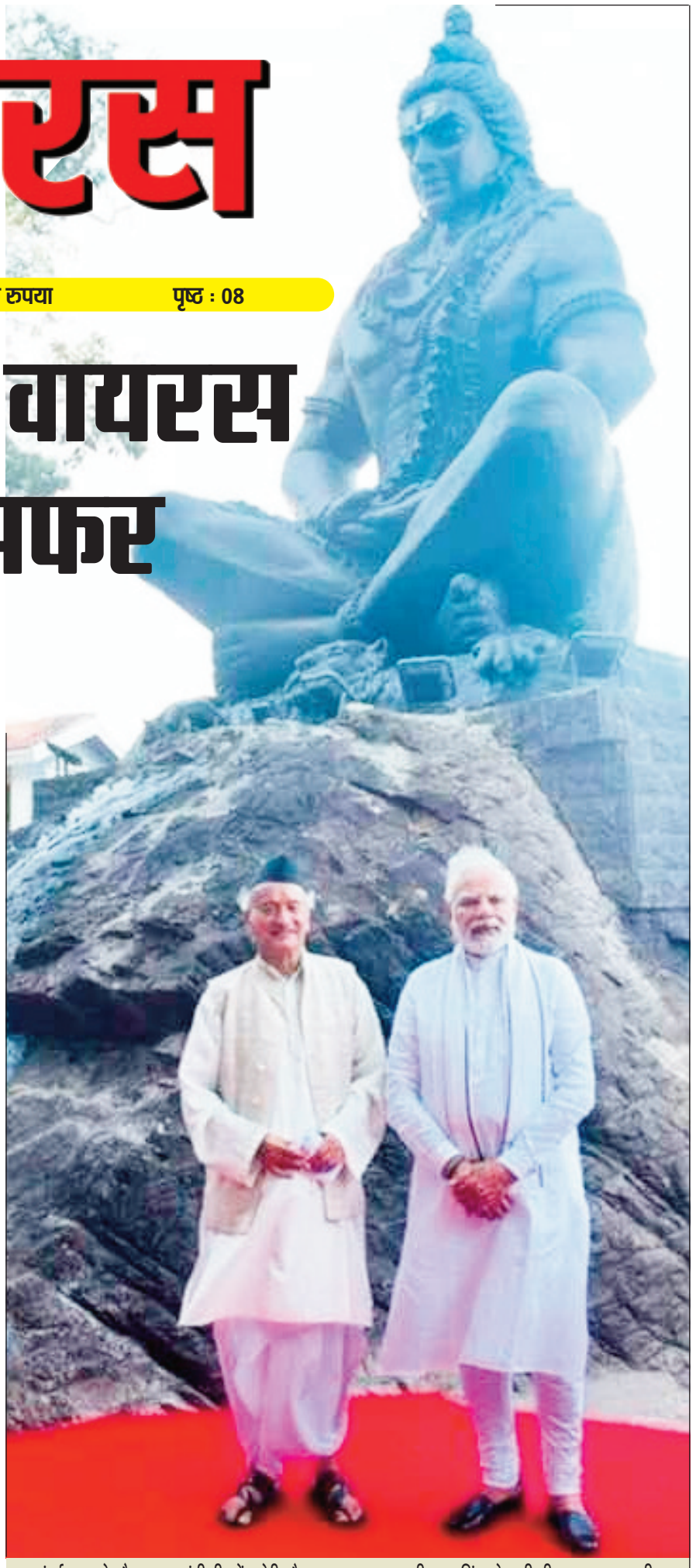

मुंबई प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और राज्यपाल, महाराष्ट्र श्री भगत सिंह कोश्यारी की एक यादगार तस्वीर

आशीष तिवारी, कार्यकारी संपादक
न्यूज़ वायरस नेटवर्क

हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मीडिया संस्थान छोटा हो या बड़ा , पत्र- पत्रिकाओं में हर दिन, हर पल, समाज को प्रभावित करने की क्षमता रही है। समाज में जो हुआ, जो हो रहा है, जो होगा, और जो होना चाहिए यानी जिस परिवर्तन की जरूरत है, इन सब पर पत्रकार को नजर रखनी होती है। आज समाज में पत्रकारिता का महत्व काफी बढ़ गया है। इसलिए उसके सामाजिक और व्यावसायिक उत्तरदायित्व भी बढ़ गए हैं। पत्रकारिता का उद्देश्य सच्ची घटनाओं पर प्रकाश डालना है, वास्तविकताओं को सामने लाना है। इसके बावजूद यह आशा की जाती है कि वह इस तरह काम करे कि 'बहुजन हिताय' की भावना सिद्ध हो।

बीते दस गौरवशाली वर्षों से यही कर रहा है आपका लोकप्रिय हिंदी दैनिक अखबार न्यूज़ वायरस ... महात्मा गांधी के अनुसार, 'पत्रकारिता के तीन उद्देश्य हैं- पहला जनता की इच्छाओं, विचारों को समझना और उन्हें व्यक्त करना है। दूसरा उद्देश्य जनता में वांछनीय भावनाएं जागृत करना और तीसरा उद्देश्य सार्वजनिक दोषों को नष्ट करना है। गांधी जी ने पत्रकारिता के जो उद्देश्य बताए हैं, उन पर कदम दर कदम आगे बढ़ते हुए इस एक दशक ले लम्बे सफर में दैनिक न्यूज़ वायरस ने अनगिनत सरकारों के दौर को देखा है। राजनैतिक उतार चढ़ाव और देश दुनिया की घटनाओं को कवर किया है लेकिन एक सिद्धांत जो पहले दिन से बनाया था वो आज भी सशक्त है और वो है सकारात्मक सोच , रचनात्मक पत्रकारिता और समाज के हितों को सर्वोपरि रखते हुए बगैर पक्षपात के सत्य का साथ देना।

मोहम्मद सलीम सैफ़ी ने टीवी जर्नलिस्म में कई दशक गुज़ारने के बाद 5,जनवरी 2009 को मीडिया कंपनी न्यूज़ वायरस नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड के नाम से अपना स्टार्टअप शुरू किया और अपने आपको जल्द ही प्रतिष्ठित फिल्म प्रोडक्शन कंपनी, टीवी न्यूज़ और कार्यक्रम निर्माता के रूप में स्थापित कर लिया, मकसद था आधुनिकता के साथ पत्रकारिता में नए प्रयोग का , लिहाज़ा 15 जून 2012 को दैनिक न्यूज़ वायरस अखबार का जन्म हुआ और शुरू हुआ देहरादून से यूपी तक दिल्ली से महाराष्ट्र तक एक नाम का मिडिया ब्रांड बनने का सफर

न्यूज़ वायरस समूह बीते 13 सालों से प्रिंट हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दोनों प्लेटफॉर्म पर पत्रकारिता के ज़रिये आपको नयी जानकारी देता है, लेकिन इतने से हमारा मकसद संतुष्ट नहीं होता है। हमारा मकसद तो हर राजनैतिक , सामाजिक घटनाओं, नई खोजों , नई जानकारियों को आप तक पहुँचाने का है। सरकार की योजनाओं और जनता की समस्याओं के बीच एक सेतु की तरह भूमिका निभाते हुए दैनिक न्यूज़ वायरस समाधान की खोज करता है। न्यूज़ वायरस समूह का मानना है कि पत्रकारिता पेशा नहीं, यह जनसेवा का माध्यम है। लोकतांत्रिक परम्पराओ की रक्षा करने शांति और भाईचारे की भावना बढ़ाने में हम हर दिन अपनी भूमिका को निभाते हुए आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ रहा है जनता का भरोसेमंद मीडिया ब्रांड न्यूज़ वायरस, दैनिक न्यूज़ वायरस, न्यूज़ वायरस नेटवर्क डॉट कॉम और ईपेपर लोकप्रियता के आयाम स्थापित कर रहे है जो लाखों लोगों का भरोसेमंद नाम बनने को ओर लगातार अग्रसर है।

यूँ तो अखबार हज़ार है लेकिन लेखनी से न्याय और जनता की अपेक्षा पर खरा कौन , कब तक और कितना उतरता है ये उसकी काबिलियत और नीयत पर निर्भर करता है , न्यूज़ वायरस समूह अपनी ख़बरों के ज़रिये हमेशा पॉजिटिव और क्रिएटिव जर्नलिस्म को बढ़ावा देता है। सकारात्मक पत्रकारिता के हमने तो दमदार 10 साल जैसे तैसे पूरे कर लिए है लेकिन सिस्टम और सरकारें नकारात्मक पत्रकारिता का ही संज्ञान क्यों लेती है, ये एक बड़ी सोच का गंभीर चिंतन होना चाहिए, सरकारों को सोचना चाहिए कि सकारात्मक पत्रकारिता करने वालो को मान, सम्मान और सहयोग मिले,कहीं ऐसा न हो कि एक दिन आर्थिक बोझ और सम्मान के अभाव में सकारात्मक पत्रकारिता करने वाले दम ना तोड़ दें ?

– यास्मीन क़मर, प्रबंध निदेशक
न्यूज़ वायरस मीडिया समूह

न्यूज़ वायरस समूह के ग्रुप एडिटर और देश के प्रतिष्ठित पत्रकार मोहम्मद सलीम सैफ़ी कहते हैं कि समाज में मानव मूल्यों को सशक्त बनने के साथ जन जीवन को विकासोन्मुख बनाना ही हमारी पत्रकारिता का दायित्व है। पत्रकारिता के सामाजिक और व्यवसायिक उत्तरदायित्व के अनेकानेक आयाम हैं। अपने इन ज़िम्मेदारियों का निर्वाह करने के लिए पत्रकार का एक हाथ हमेशा समाज की नब्ज पर होता है तो दुसरा सरकार की कार्यशैली और प्रशासनिक व्यवस्था पर .. सकारात्मक सोच और लोक कल्याण से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाते हुए आज न्यूज़ वायरस समूह एक विशाल वृक्ष की भांति न सिर्फ उत्तराखंड , उत्तर प्रदेश में भरोसेमंद मीडिया ब्रांड बना है बल्कि रचनात्मकता और रोचकता के साथ सम सामयिक विषयों से पाठकों को रूबरू कराना ही हिंदी दैनिक न्यूज़ वायरस , टीवी न्यूज़ वायरस, पोर्टल न्यूज़ नेटवर्क डॉट कॉम और ईपेपर का सकारात्मक नज़रिया ही न्यूज़ वायरस का एकमात्र लक्ष्य है।

समूह की प्रबंध निदेशक श्रीमती यास्मीन क़मर, सलाहकार मो. शादान सलीम व इफरा सलीम को महामहिम राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी आशीर्वाद देते हुए साथ में समूह संपादक मो सलीम सैफी।

बधाई हो : आपकी औसत उम्र दो साल बढ़कर हुई 69.7 वर्ष

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

भारतीयों की औसत आयु अब दो साल बढ़कर 69.7 वर्ष हो गई है। हालांकि यह अभी भी वैश्विक औसत जीवन प्रत्याशा (जीवन काल) 72.6 वर्ष से कम है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (एसआरएस) के अनुसार जीवन प्रत्याशा में दो साल की वृद्धि होने में 10 वर्ष लग गए। हालांकि जीवन प्रत्याशा को तेजी से आगे बढ़ाने में शिशु और नवजात मृत्यु दर में कमी भी एक बड़ी वजह है। सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा देश की राजधानी में 75.9 वर्ष और सबसे कम छत्तीसगढ़ में 65.3 वर्ष दर्ज की गई। वर्ष 1970-75 में भारत की जीवन प्रत्याशा 49.7 थी, जो वर्ष 2015-2019 में 69.7 हो गई यानी 45 वर्षों के अंतराल में औसत आयु 20 वर्ष बढ़ी।

शिशु मृत्यु दर घटने से पड़ा सकारात्मक प्रभाव

रिपोर्ट के अनुसार जन्म के समय और एक या पांच वर्ष की आयु में जीवन प्रत्याशा का अंतर उन राज्यों में सर्वाधिक है, जहां उच्च शिशु मृत्यु दर ज्यादा है जैसे- मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, ऐसा राज्य है, जहां शिशु मृत्यु दर (38) दूसरे नंबर पर है। यहां जैसे ही एक वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में कमी आई, जीवन प्रत्याशा में 3.4 वर्षों की वृद्धि हो गई। इसी तरह मध्यप्रदेश में शिशु मृत्यु दर (43) सर्वाधिक है, यहां भी बच्चों ने जब एक वर्ष की आयु पूरी की तो जीवन प्रत्याशा में 2.7 वर्षों का इजाफा हो गया।

शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की प्रत्याशा में बढ़ा अंतरवर्ष 2015-19 के लिए गांवों में जीवन प्रत्याशा 68.3 वर्ष और शहरों में 73.0 वर्ष रही। इसी तरह ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में क्रमशः 0.3 वर्ष और 0.4 वर्ष की वृद्धि हुई है।

जीने की औसत उम्र यहां ज्यादा

राज्य	पुरुष	महिलाएं	जीवन काल
दिल्ली	74.3	77.5	75.9
केरल	72.3	78	75.2
जम्मू-कश्मीर	72.6	76.1	74.2
हिमाचल प्रदेश	69.9	77.1	73.1
पंजाब	71.1	74.7	72.8

निचले पायदान पर ये पांच राज्य

राज्य	पुरुष	महिलाएं	जीवन काल
राजस्थान	66.8	71.3	69
असम	66.8	68.3	67.5
मध्य प्रदेश	65.2	69.1	67
उत्तर प्रदेश	65	66.2	65.6
छत्तीसगढ़	63.7	66.9	65.3

(सभी आकड़े वर्षों में)

भारत में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की जीवन प्रत्याशा में बड़ा अंतर है। जैसे हिमाचल प्रदेश में शहरी महिलाओं की जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक 82.3 वर्ष है, जबकि छत्तीसगढ़ में ग्रामीण पुरुषों की सबसे कम केवल 62.8 वर्ष है। असम में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की जीवन प्रत्याशा में लगभग आठ वर्ष का अंतर है। इसके बाद पांच वर्ष का अंतर हिमाचल प्रदेश में है। केरल एकमात्र ऐसा राज्य है, जहां ग्रामीण जीवन प्रत्याशा पुरुषों और महिलाओं, दोनों की शहर से अधिक है।

दुनिया में जापानी जीते हैं सर्वाधिकजन्म के समय बांग्लादेश की जीवन प्रत्याशा 72.1 वर्ष और नेपाल की 70.5 वर्ष है। इन दोनों ही देशों में शिशु मृत्यु दर भारत से कम है।विश्व में जापान के लोग जीते हैं सर्वाधिक। यहां की जीवन प्रत्याशा 85 वर्ष हैनॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड की जीवन प्रत्याशा है 83 वर्षसेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक की जीवन प्रत्याशा सबसे कम 54 वर्ष है।

मैक्स हॉस्पिटल के रक्तदान शिविर में 54 लोगों ने किया रक्तदान

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

मैक्स हॉस्पिटल देहरादून ने रक्तदान दिवस पर देहरादून में स्वेच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जिसमें 54 लोगो ने रक्तदान किया। शहर के कई महत्वपूर्ण शख्सियतों ने हिस्सा लिया। रक्तदान करने वाले लोगों को मैक्स हॉस्पिटल ने प्रशस्ति पत्र से सम्मानित भी किया ।

आपको बता दें कि रक्तदान शिविर सुबह 10 से शाम 4 बजे तक आयोजित किया गया

इसमें 18 से 60 वर्ष तक के आयु के सभी स्वस्थ महिला एवं पुरुष रक्तदान किया। इस

शिविर में शारीरिक जांच व अन्य कई तरह की जांच जैसे की आँखों की जांच निशुल्क की गयी।

स्वेच्छिक रक्तदान शिविर में मैक्स हॉस्पिटल के ट्रांसफ्यूज़न मेडिसिन के एसोसिएट कंसलटेंट डॉ विनय कुमार ने कहा कि, लोगों द्वारा रक्तदान करने से दिल की सेहत में सुधार, दिल की बीमारियों और स्ट्रोक के खतरे को कम माना जाता है। खून में आयरन की ज्यादा मात्रा दिल के दौरे के खतरे को बढ़ा सकती है। नियमित रूप से रक्तदान करने से आयरन की अतिरिक्त मात्रा नियंत्रित हो जाती है, जो दिल की सेहत के लिए अच्छी है।

उन्होंने बताया कि कई बार मरीजों के शरीर में खून की मात्रा इतनी कम हो जाती है कि उन्हें किसी और व्यक्ति से ब्लड लेने की आवश्यकता पड़ जाती है। ऐसी ही इमरजेंसी स्थिति में खून की आपूर्ति के लिए लोगों को रक्तदान करने के लिए आगे आना चाहिए। इससे जरुरत मंद की मदद हो सकेगी।

राजधानी देहरादून में एसी-कूलर सब बेकार, पारा 40 डिग्री पार

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

दून व आसपास के इलाकों में बारिश होने के बाद दो दिन गर्मी से थोड़ी राहत मिली, लेकिन सोमवार को सूरज ने फिर आंखें तरेर लीं और अधिकतम तापमान 41.3 डिग्री पर पहुंच गया। न्यूनतम तापमान भी 25.3 डिग्री दर्ज किया गया। देहरादून की बात करें तो पिछले 15 दिनों से अधिकतम तापमान 40 डिग्री के आसपास बना हुआ है। लिहाजा लोगों को पिछले 15 दिनों से जबरदस्त गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। पिछले एक दशक का गर्मी का रिकॉर्ड भी टूट चुका है।

हालांकि, मौसम विज्ञानियों ने संभावना जताई कि 15 जून से मैदान से लेकर पहाड़ तक बारिश के आसार हैं, लेकिन जिस तरीके से सूरज ने आंखें तरेरी हैं, उसे देखते हुए मौसम विज्ञानी भी भौचक हैं।

उधर, मौसम विभाग के मुताबिक, अगले 24 घंटे में दून में अधिकतम तापमान 42 और न्यूनतम 25 डिग्री रहने की संभावना है। रिपोर्ट के मुताबिक, सोमवार को पंतनगर में 39.9 डिग्री,

मुक्तेश्वर 29.6 डिग्री और टिहरी में 29 डिग्री अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। वहीं, मौसम विज्ञानियों ने अगले 24 घंटों में उत्तरकाशी, और चमोली जिलों में कहीं-कहीं गर्जना के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है,

हिंदी दैनिक

न्यूज़ वायरस

वर्ष : 10 अंक : 312 | देहरादून, बुधवार, 15 जून, 2022 | मूल्य : एक रुपया | पृष्ठ : 08

सदन में 'अपात्र को ना और पात्र को हां' मुहिम का उठा मुद्दा : मंत्री रेखा आर्या ने साधा विपक्ष पर निशाना

8

विधानसभा सत्र : पहले दिन कदमताल करता दिखा पक्ष विपक्ष

उत्तराखंड विधानसभा में नहीं देखा होगा ऐसा नज़ारा

देखिये उत्तराखंड सरकार का विपक्ष के संग कदमताल

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

मुख्यमंत्री धामी ने अपने पूर्व कैबिनेट सहयोगी और मौजूदा नेता विपक्ष यशपाल आर्य के संग जो मित्रवत व्यहवार विधान सभा सत्र के पहले दिन की शुरुआत में दिखाई है वो आप भी देखिए। इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि पहले मुख्यमंत्री धामी ने नेता विपक्ष से मुलाकात कर उन्हें शुभकामनाये दी फिर अपने अपने कक्ष से निकल कर मुख्यमंत्री धामी और विपक्ष के नेता यशपाल आर्य एक साथ पहली मंजिल से उतरकर साथ साथ कदमताल करते हुए सभा मंडप की और जा रहे हैं। ये लम्हे साफ़ बयां करते हैं की सदन के अंदर पक्ष और विपक्ष के बीच जंग नहीं दोस्ताना माहौल होने वाला है। ये अलग बात है कि जनता को उम्मीद होती है कि उनके मुद्दों पर जहाँ सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाएगी तो वही विपक्ष सरकार की विफलताओं पर उसे सदन में घेरेगी और तीखे ज़ुबानी हमले कर जन आवाज़ को बुलंद करेगी। लेकिन जब सदन के बाहर ऐसा नज़ारा आप देख रहे हैं तो अंदर क्या सुरते हाल होगी खुद अंदाज़ा लगाइये। राजनैतिक पंडित इसको शार्प सीएम धामी की चतुर चाल बता कर कहते हैं कि इस तरह का बड़ा दिल दिखाते हुए मुख्यमंत्री बताना चाहते हैं कि उन्हें अपने सियासी प्रतिद्वंदियों को जादू की झप्पी से हराना खूब आता है। तभी तो कुछ दिन पहले उनकी तस्वीरें पूर्व सीएम हरीश रावत के संग भी खूब चर्चाओं में रही थी। तो क्या अब नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के संग सरकार की ये जुगलबंदी कहीं फ्रैंडली मैच का ही इशारा तो नहीं है।

विधानसभा में महिला विधायकों को मिला विशेष कक्ष एक उपलब्धि : ऋतू खंडूरी भूषण

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

विधानसभा सत्र के पहले दिन विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूडी भूषण ने नई शुरुआत करते हुए महिला विधायकों, अधिकारियों एवं महिला मीडियाकर्मियों की सुविधा को देखते हुए विधानसभा भवन में महिलाओं के लिए विशेष कक्ष का शुभारंभ किया।

विधानसभा अध्यक्ष बनते ही ऋतु खंडूडी ने विधानसभा परिसर में महिला विधायक, अधिकारियों एवं महिला मीडियाकर्मियों के लिए एक विशेष कक्ष बनाए जाने की प्राथमिकता के आधार पर इच्छा जाहिर की थी । जिसके बाद मंगलवार से शुरू हुए बजट सत्र के पहले दिन इस विशेष कक्ष का शुभारंभ विधानसभा अध्यक्ष द्वारा किया गया । आपको बता दें कि उत्तराखंड की पांचवीं विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष सहित आठ महिला विधायक हैं ।

राज्य बनने के बाद विधानसभा भवन में महिला विधायकों के लिए इस प्रकार के कक्ष की कोई भी व्यवस्था नहीं थी, ऋतु खंडूडी भूषण ने महिला विधायक होते हुए खुद भी इस समस्या का जिक्र इससे पहले कार्यकाल में विधायक रहते हुए किया था । स्पीकर ऋतु खंडूडी ने कहा कि यह विशेष कक्ष महिला विधायकों को सत्र के दौरान अपनी तैयारी एवं भोजन अवकाश या स्थगन के दौरान बैठने की जगह के लिए बनाया गया है। उन्होने कहा की सत्र स्थगन के दौरान विधायक हॉस्टल तक आने जाने में दिक्कतें रहती हैं। उन्होंने कहा कि इस समस्या को उन्होंने खुद भी झेला है। इसलिए विधानभवन में अलग कक्ष तैयार किया गया है।

इस दौरान महिला विधायकों द्वारा भी विशेष कक्ष बनाए जाने पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए विधानसभा अध्यक्ष का आभार व्यक्त किया गया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य, विधायक रेणु बिष्ट, ममता राकेश, अनुपमा रावत, सविता कपूर, सरिता आर्य, शैला रानी रावत, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, सचिव राधिका झा, वरिष्ठ पत्रकार ज्योत्सना बौंठियाल मौजूद रही।

बजट सत्र : महाराज के जवाब से विपक्ष क्लीन बोल्ड, विपक्ष का बाउंसर हुआ बेअसर

सदन में मंत्री सतपाल महाराज ने अनुभव का दिखाया ट्रेलर, नतमस्तक हुए सवाल

आशीष तिवारी
न्यूज़ वायरस नेटवर्क

अगर अनुभव बोलता है तो सामने कोई भी हो ख़ामोशी से सुनता है कुछ ऐसा ही नज़ारा दिखा सदन के अंदर तब दिखा जब टीम धामी के सबसे भरोसेमंद मिनिस्टर ने मोर्चा सम्हाला। इसके बाद तो विपक्ष के सवाल का हर बाउंसर मंत्री महाराज के सटीक जवाबों से बेअसर हो गया। विधानसभा सत्र के पहले दिन ही प्रदेश के पर्यटन, लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने सदन में पूछे गए सभी प्रश्नों के सकारात्मक और बेबाकी से जवाब देते हुए विपक्ष को अपनी कुशलता और अनुभव का बखूबी नमूना पेश किया है।

विधानसभा के द्वितीय सत्र के पहले दिन प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने विपक्ष द्वारा उन्हें घेरने की रणनीति को फेल करते हुए सदन के अंदर पूछे गए सभी प्रश्नों के बेबाकी से जवाब देकर निरुत्तर कर दिया। विपक्ष की ओर विधायक प्रीतम सिंह ने पर्यटन मंत्री से सवाल किया कि था कि वर्ष 2022 में चारधाम यात्रा में अब तक कितने तीर्थ यात्री दर्शन हेतु आए हैं और अब तक कितने तीर्थ यात्रियों की मृत्यु हुई है। इस पर प्रश्न का सटीक उत्तर देते हुए पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने सदन को बताया कि कपाट खुलने की तिथि से 10 जून 2022 तक चारों धामों में 19,19,923 तीर्थयात्री दर्शनों हेतु आए हैं और व्यवस्थाओं के अभाव में किसी भी यात्री की मृत्यु नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि जिन भी यात्रियों की मृत्यु हुई है उनमें अधिकतर यात्रियों की मृत्यु हृदय गति रुकने के कारण हुई है। इसके अतिरिक्त सड़क दुर्घटनाओं के कारण भी मृत्यु हुई है।

सदन में जब विपक्ष ने जब पर्यटन मंत्री से सवाल किया कि प्रदेश में होम स्टे की क्या नीति है तो उन्होंने सदन को अवगत कराया कि राज्य में पर्यटन विभाग द्वारा होम स्टे हेतु अतिथि उत्तराखंड गृह आवास (होम स्टे) पंजीकरण नियमावली, 2015 और दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास(होम स्टे) विकास योजना, 2018, दो प्रकार की नीति संचालित की जा रही है।हरिद्वार में कनखल अनूपपुर गंगा दासपुर होकर बालावाली तक गंगा नदी पर बनी है उत्सव के समानांतर सड़क के निर्माण के प्रस्ताव पर विधायक अनुपमा रावत के सवाल के जवाब में लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने सदन को अवगत कराया कि मुख्यमंत्री की घोषणा के अंतर्गत उक्त उक्त सड़क के प्रथम चरण के कार्यों जैसे भूमि की व्यवस्था, सर्वेक्षण, डीपीआर गठन हेतु 32.50 किलोमीटर लंबाई के लिए 97.50 लाख की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

विधायक ममता राकेश ने सदन के अंदर पूछे गए प्रश्न के माध्यम से सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज से पूछा कि जनपद हरिद्वार के अंतर्गत भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र को केंद्रीय जल आयोग सी.डब्लू.सी. द्वारा क्रिटिकल जोन घोषित कर दिया गया है, जिस कारण नए नलकूप आदि का निर्माण ना होने से किसानों को सिंचाई की समस्या हो रही है। प्रश्न का उत्तर देते हुए सिंचाई मंत्री ने सदन को अवगत कराया कि क्षेत्र विशेष का जोन निर्धारण सेंट्रल ग्राउंड वॉटर बोर्ड द्वारा भू-जल की उपलब्धता के अनुरूप किया जाता है। क्षेत्र में भू-जल की उपलब्धता में वृद्धि होने पर संबंधित क्षेत्र को सेमीस्टिकल जोन से बाहर निकालने की कार्यवाही सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड द्वारा की जानी संभव है। सदन में जब विधायक संजय डोभाल ने ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत स्तर पर भ्रष्टाचार के मामलों पर चल रही कार्यवाही के विषय में पंचायत मंत्री सतपाल महाराज इस सवाल किया तो उन्होंने सदन को बताया कि प्रदेश के ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत में भ्रष्टाचार के कुल 23 मामले लंबित हैं और इन सभी मामलों में कार्यवाही की जा रही है।विधानसभा सदस्य फुरकान अहमद ने सदन में संस्कृति मंत्री से जानना चाहा कि पिरान कलियर दरगाह रुड़की, जनपद हरिद्वार को पांचवा धाम घोषित करने पर क्या सरकार विचार कर रही है? इस सवाल के जवाब में संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि पिरान कलियार दरगाह, रुड़की, जनपद हरिद्वार को पांचवा धाम घोषित किया जाना संस्कृति विभाग के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। इस क्षेत्र में लगने वाले मेले को विभाग द्वारा सूचिबद्ध किया गया है।

कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने इसी प्रकार विपक्ष के तमाम सवालों का सकारात्मक और बेबाकी से जवाब देते हुए सदन विपक्ष को अपने सटीक होमवर्क , शानदार अनुभव और प्रभावशाली बयानों से संतुष्ट कर दिया है। देखना होगा कि आगे आने वाले दिनों में विपक्ष फिर किस तरह की रणनीति से मंत्री महाराज को घेरने की तैयारी करेगा।

धामी सरकार ने पेश किया 65,571.49 करोड़ का बजट , जानिए पूरा लेखा जोखा

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने अपना पहला बजट पेश कर दिया है. 2022-23 के लिए 65571.49 करोड़ का बजट पेश किया है. प्रदेश की कुल राजस्व प्राप्तियां 63,774.55 करोड़ की हैं. जबकि कुल एक्सपेंडीचर 65,571.49 करोड़ का है... वर्ष 2022-23 में राजस्व प्राप्तियों में रु 51,474.27 करोड़ राजस्व आय अनुमानित है. वर्ष 2022-23 में आय-व्ययक अनुमान में कर राजस्व रु 24,500.72 करोड़ की प्राप्ति अनुमानित है. स्वयं का कर राजस्व रु 15,370.56 करोड़ और करेत्तर राजस्व के अन्तर्गत रु 5,520.79 करोड़ की प्राप्ति अनुमानित है. वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल प्राप्तियाँ रु 63,774.55 करोड़ अनुमानित है... पेंशन की मद में रु 6,703.10 करोड़ का प्रावधान किया गया है. ब्याज भुगतान हेतु रु 6,017.85 करोड़ का प्रावधान किया गया है. राज्य सरकार द्वारा पोषित 'नंदा गौरा योजना के अंतर्गत रु 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है.

योजनाओं के लिए इतना बजट:

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रु 311.76 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है. स्मार्ट सिटी योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में रु 205 करोड़ का प्रावधान किया गया है. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रु 105.41 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में रु 112.38 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है.

पेंशन के लिये इतने पैसे:

सभी पात्र वृद्धजनों, निराश्रित विधवाओं, दिव्यांगों, आर्थिक रूप से कमजोर किसानों, परित्यक्त महिलाओं को पेंशन दिये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रु 1500 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है. उत्तराखण्ड की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु सभी गरीब परिवारों को अन्त्योदय कार्ड धारकों को एक वर्ष में तीन (03) निःशुल्क एलपीजी सिलेण्डर के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु रु 55.50 करोड़ का प्रावधान किया गया है.

ओपन जिम और गौसदन के लिये बजट:

सामुदायिक फिटनेस उपकरण (ओपन जिम) हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रु 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है. गौसदनों की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रु 15 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है.

बागवानी और चाय विकास का बजट:

मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास योजना' के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में रु 17 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है. चाय विकास योजना' हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रु 18.40 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है.मेरा गांव, मेरी सड़क के लिए बजटः मेरा गांव, मेरी सड़क के अन्तर्गत प्रत्येक विकासखण्ड में दो सड़क निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रु 13.48 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है. अटल उत्कर्ष विद्यालय' योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रु 12.28 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है.

57 हजार करोड़ से ज्यादा था 2021-22 का बजट:

उत्तराखंड विधानसभा में तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वित्तीय वर्ष 2021—22 के लिए 57,400.32 करोड रुपये का बजट पेश किया था. पिछले बजट में हेल्थ, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार को बढ़ावा और कृषि पर खास जोर दिया गया था. पिछले बजट में विभिन्न माध्यमों से सरकार की कुल आय 57,024.22 लाख रुपये अनुमानित की गई थी. जिसमें राजस्व प्राप्तियां 44,151.24 करोड रुपये अनुमानित थीं. टैक्स से 20,195.43 करोड़ रुपये अनुमानित था. बजट में राजस्व व्यय 44,036.31 करोड रुपये जबकि पूंजीगत व्यय 13,364.01 करोड रुपये रहने का अनुमान रखा गया था.

एसटीएफ उत्तराखंड ने ज़मीन की धोखाधड़ी में इनामी बाबा को हापुड़ से दबोचा

भूमा निकेतन आश्रम जनपद हरिद्वार के मैनेजर राजेंद्र शर्मा की ओर से थाना ज्वालापुर में दर्ज कराए गए जमीन की धोखाधड़ी के एक मामले में वांछित दस हजार के इनामी अपराधी वेद प्रकाश शर्मा उर्फ वेदानंद सरस्वती को एसटीएफ देहरादून द्वारा कस्बा हापुड़ जनपद हापुर उत्तर प्रदेश में दबिश देकर गिरफ्तार किया गया । इसकी गिरफ्तारी के लिए वरिष्ठ पुलिस हरिद्वार द्वारा कुछ रोज पहले 10000 के इनाम की घोषणा की गई थी आपको यहाँ बता दें कि भूमा निकेतन आश्रम के मैनेजर राजेंद्र शर्मा द्वारा अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित किया गया था कि भूमा निकेतन आश्रम के पीछे करीब 9120 वर्ग मीटर जमीन को कई वर्ष पूर्व में उनके आश्रम द्वारा खरीद कर लिया गया था लेकिन वेदानन्द सरस्वती आदि अभियुक्त गणों द्वारा फर्जी दस्तावेजों के आधार पर धोखाधड़ी की नियत से उसी जमीन को दोबारा से किसी और को बेच दिया गया इस जमीन की कीमत आज करोड़ों में है वेदानंद सरस्वती को गिरफ्तार करने के लिए पिछले काफी समय से हरिद्वार पुलिस लगातार प्रयास कर रही थी। वेदानंद सरस्वती के बारे में जानकारी मिली की यह अपने आप को शारदा आश्रम का ट्रस्टी बताता है तथा जमीन की धोखाधड़ी को लेकर पूर्व में दो बार जेल जा चुका है। वेदानंद सरस्वती वर्ष 1998 थाना ज्वालापुर धारा 307 आईपीसी दूसरी पार्टी पर जमीन को लेकर जान से मारने की नियत से फायर करने के मामले में लोवर कोर्ट हरिद्वार से आजीवन कारावास की सजा पाए है तथा हाई कोर्ट से बेल पर बाहर है। इसके अलावा वर्ष 2009 थाना क्लेमेंट टाउन निवासी देवेंद्र मित्तल से 8:30 बीघा जमीन की खरीदारी में लाखों रुपए का फर्जी ड्राफ्ट दे जाने को लेकर थाना क्लेमेंट टाउन देहरादून धारा 420 आई पीसी का मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसमें यह अपने भाई मुकेश गौड़ व बेटा सचिन के साथ सुद्दोवाला देहरादून जिला कारागार में छह-सात महीने जेल में रह चुका है ।

अग्निवीरों को पुलिस की भर्ती में प्राथमिकता देगा उत्तराखंड : मुख्यमंत्री

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 'अग्निपथ योजना' के माध्यम से नौजवानों के लिए भारतीय सेना के द्वार खोलने हेतु माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि 'अग्निपथ योजना' के माध्यम से भारत की सैन्य ताकत को मजबूती मिलने के साथ ही युवाओं की कौशलता और प्रतिबद्धता में भी खासा सुधार आएगा।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भारतीय रक्षा व्यवस्था को लेकर पिछले कुछ सालों में कई बड़े सुधार देखने को मिले हैं। अग्निपथ योजना को लागू करने का जो निर्णय लिया गया है, उससे देश के नौजवान चार साल की सेवा सेना में दे सकेंगे। इस योजना से अग्निवीर तैयार किए जाएंगे, देश के नौजवान आर्म फोर्स में जा सकेंगे। उन्हें नई तकनीक से ट्रेंड किया जाएगा और देश को हाई स्किल आर्म फोर्स मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय सेना को विश्व की बेहतरीन सेना बनाने की दृष्टि से यह ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। युवाओं को चार साल के लिए सेना में भर्ती कराया जाएगा, इस दौरान अग्निवीरों को अच्छा वेतन मिलेगा। सेना की चार साल की नौकरी के बाद युवाओं को भविष्य के लिए अन्य अवसर दिए जाएंगे। चार साल की नौकरी के बाद सेवा निधि पैकेज मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत जो जवान चार साल बाद यहाँ से निकलेंगे, उत्तराखण्ड सरकार ऐसे अग्निवीरों को पुलिस की भर्ती में प्राथमिकता से अवसर देगी। 17 साल 06 माह से 21 साल के युवा, 10/12वीं के छात्र आवेदन कर सकेंगे। अगर कोई अग्निवीर देश सेवा के दौरान शहीद हो जाता है, तो उसके परिजनों को सेवा निधि के अन्तर्गत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि ब्याज समेत मिलेगी, इसके अलावा बाकी बची नौकरी का भी वेतन दिया जाएगा। वहीं अगर कोई अग्निवीर डिसेबल हो जाता है, तो उसे 44 लाख रुपए तक की राशि दी जाएगी, इसके अलावा बाकी बची नौकरी का भी वेतन मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हमेशा देश के सैनिकों का मनोबल बढ़ाने का कार्य किया है। सैनिकों की अनेक लंबित मांगों की स्वीकृतियां प्रदान की। आज भारत रक्षा के क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा है।

काम की बात में जानिए मेडिकल नेगलिजेंस की कहां करें शिकायत

महविश की रिपोर्ट
न्यूज़ वायरस नेटवर्क

मेडिकल नेगलिजेंस यानी इलाज के दौरान लापरवाही पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। दरअसल पटियाला की एक महिला की गॉल ब्लैडर स्टोन निकालने के दौरान मौत हो गई थी। मामला 18 साल पुराना है। कोर्ट ने लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉ गुरमीत सिंह को इस केस का दोषी माना। डॉक्टर को मृतक महिला के परिवार को 25 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर देने का आदेश दिया।

आज न्यूज़ वायरस पर जरूरत की खबर में जानते हैं कि मेडिकल नेगलिजेंस क्या है? इसके खिलाफ कैसे और कहां शिकायत की जा सकती है...

सवाल– मेडिकल नेगलिजेंस का मतलब क्या है ?

जवाब– जब कोई डॉक्टर या मेडिकल स्टाफ किसी मरीज के इलाज या देखभाल में लापरवाही करता है। जैसे कि गलत तरीके से दवा देना, गलत तरीके से सर्जरी, मेडिकल गाइडेंस गलत देना, सर्जरी के दौरान मरीज को नुकसान पहुंचाना ये सब मेडिकल नेगलिजेंस के अंदर आता है। क्योंकि, इसकी वजह से मरीज को नुकसान पहुंचता है और उसकी मौत तक हो जाती है।

सवाल– मेडिकल नेगलिजेंस हुआ है इसे कैसे तय किया जाता है ?

जवाब– कोई व्यक्ति किसी अस्पताल या डॉक्टर के पास इस उम्मीद के साथ जाता है कि वहां उसका सही तरीके से इलाज किया जाएगा। डॉक्टर की ड्यूटी है कि वह यह तय करे कि मरीज का इलाज कैसे करना है। इसके लिए क्या-क्या करना होगा, कौन-सी दवाई देनी है कौन सी नहीं। जब डॉक्टर या मेडिकल स्टाफ अपनी ड्यूटी सही तरीके से नहीं निभाता तो इसे इलाज में लापरवाही माना जा सकता है।

सवाल– मेडिकल नेगलिजेंस को लेकर कोई कानून है या नहीं ?

जवाब– हां, इसके लिए कानून है। कई बार स्किल्ड डॉक्टर से भी लापरवाही हो जाती है। ये लापरवाही किसी व्यक्ति के जीवन और मौत से

जुड़ी है। इसलिए इससे अपराध माना गया है। ऐसे मामलों में डॉक्टर, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम या हेल्थ सेंटर के खिलाफ केस किया जा सकता है।

सवाल– मेडिकल नेगलिजेंस की शिकायत कैसे दर्ज करा सकते हैं?

जवाब- इन तरीकों से शिकायत कर सकते हैं...

मेडिकल सुपरिडेंट को लिखित शिकायत कर सकते हैं।शिकायत करने के बाद इसकी कॉपी CMO (चीफ मेडिकल ऑफिसर) को देनी होगी।

अगर CMO का कोई जवाब नहीं आ रहा है या फिर आप उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हैं तो आप अपने राज्य के मेडिकल काउंसिल में शिकायत कर सकते हैं।अगर मेडिकल नेगलिजेंस की वजह से जान चली जाती है या जान को खतरा होता है तो स्थानीय पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।डॉक्टर इलाज में लापरवाही करता है तो उस पर क्रिमिनल और सिविल दोनों तरह का केस बनता है।

डॉक्टर के खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत भी मुकदमा किया जा सकता है।

क्रिमिनल केस के मामले में अपराध के इरादे को साबित करना बहुत जरूरी होता है।जब डॉक्टर क्रिमिनल केस में दोषी साबित हो जाता है, तब उसे जेल की सजा हो सकती है।सिविल केस में पीड़ित नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए मुआवजे का दावा कर सकता है।

क्रिकेट को बदनाम करने वालों के खिलाफ लड़ेंगे कानूनी लड़ाई' : महिम वर्मा, सचिव, सीएयू

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड ने उन पर लगे आरोपों पर कड़ी नाराज़गी ज़ाहिर करते हुए अब फ्रंट पर इस लड़ाई को लड़ने का मन बना लिया है। एसोसिएशन के सचिव खुद मैदा के साने आये और कहा कि कुछ लोगों द्वारा भ्रामक खबरें फैलाकर एसोसिएशन की गरिमा को धूमिल किया गया है... असत्य और भ्रामक जानकारी के साथ सीएयू को बदनाम किया जा रहा है और ऐसे लोगों के खिलाफ एसोसिएशन कार्रवाई कानूनी लड़ने जा रहा है...

एसोसिएशन के सचिव माहिम वर्मा का कहना है कि सत्र 2019 और 20 में खिलाड़ियों को 1250 रुपये प्रतिदिन की दर से डीए का भुगतान किया गया है, जिसका लेजर उपलब्ध है.... इसके अलावा सत्र 2020 -21 में बोर्ड के सभी टूर्नामेंट बायो बबल में आयोजित किए गए, जिसमें सभी खिलाड़ियों के रहने और खाने की व्यवस्था बीसीसीआई के दिशा निर्देशों के अनुरूप उनके द्वारा चयनित होटलों में की गई थी... वहां खाने का सामान बाहर से मंगवाने और खिलाड़ियों के बायो बबल से बाहर जाने पर भी प्रतिबंध था... इसलिए सीएयू की तरफ से खिलाड़ियों और अन्य सबको तीनों टाइम का भोजन मुहैया कराया गया और नियमानुसार उनके मील पर खर्च धनराशि को उनके डीए से काट कर शेष डीए की धनराशि सभी को उनके अकाउंट में ट्रांसफर की गई...

उन्होंने आगे कहा कि एसोसिएशन पर दूसरा आरोप यह भी लगाया जा रहा है कि सीएयू द्वारा टूर्नामेंट और ट्रायल में फूड और कैटरिंग के नाम पर करीब पौने दो करोड़ रुपए खर्च किए गए... जबकि हकीकत यह है कि सत्र 2019- 20 में एसोसिएशन ने करीब 100 से अधिक बोर्ड मैचों का आयोजन किया... इसके अलावा महिला और पुरुष खिलाड़ियों के ट्रायल कैंप और प्रैक्टिस मैच भी आयोजित किए... लेकिन केले और पानी के मद में खर्च की गई धनराशि के संबंध में भ्रम फैलाया जा रहा है...

ये हैं वो तथाकथित आरोप -

क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड पर अनिमितताओं और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है... आरोप है कि 2020-21 की ऑडिट रिपोर्ट में CAU ने टूर्नामेंट के ट्रायल मैच में भोजन खानपान में 1,74,7346 दैनिक भत्तों पर खर्च किए... साथ ही पानी की बोतलों पर 35 लाख और केलों पर 22 लाख का खर्चा बताया है... जबकि खिलाड़ियों को मात्र 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से डीए का भुगतान किया गया...

तीर्थ यात्रियों को उपलब्ध की जायेगी बेहत्तर सुविधा : धन सिंह रावत, स्वास्थ्य मंत्री

यात्रा मार्गों पर बेहत्तर स्वास्थ्य सेवाओं के लिये विशेषज्ञ समिति गठित

चार धाम में स्वास्थ्य सुविधाओं का निरीक्षण कर समिति देगी सुझाव

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

प्रदेश में संचालित चारधाम यात्रा में स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों को दूर करने के उद्देश्य से चार सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठित कर दी गई है। समिति चार धाम सहित यात्रा मार्गों पर स्वास्थ्य सुविधाओं का निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपेगी। इसके साथ ही समिति केदारनाथ धाम में स्थित स्क्रीनिंग प्वाइंट एवं हेल्थ फैसिलिटिज का भी मुआयना करेगी। तीर्थ यात्रियों को बेहत्तर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिये हर स्तर पर प्रयास किये जा रहे हैं।

सूबे के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ0 धन सिंह रावत ने बताया कि प्रदेश में संचालित चार धाम यात्रा में स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों को दूर किया जायेगा। उन्होंने बताया कि यात्रा मार्गों पर तीर्थ यात्रियों को बेहत्तर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चार सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन कर दिया गया है। जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखंड की निदेशक डॉ0 सरोज नैथानी करेंगी।

समिति में दून मेडिकल कॉलेज के टी0बी0 एवं चेस्ट विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ0 अनुराग अग्रवाल, कार्डियोविभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ0 अमर उपाध्याय एवं हिमालयन मेडिकल कॉलेज देहरादून के मेडिसिन विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ0 नवीन राजपूत शामिल हैं। डॉ0 रावत ने बताया कि समिति चार धाम सहित यात्रा मार्गों पर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपेगी। उन्होंने बताया कि समिति विशेषकर आपातकालीन सेवाएं एवं चार धामों में तीर्थ यात्रियों की आकस्मिक मृत्यु को दृष्टिगत रखते हुये स्वास्थ्य सेवाओं में आवश्यक सुधार किये जाने को लेकर अपने सम्पूर्ण सुझाव देने के लिये अधिकृत है, ताकि चारधाम यात्रा में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुदृढ कर और अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

डॉ0 रावत ने बताया कि समिति केदारनाथ धाम में स्थित स्क्रीनिंग प्वाइंट एवं हेल्थ फैसिलिटिज का भी निरीक्षण करेगी। उन्होने बताया कि राज्य में आने वाले प्रत्येक तीर्थ यात्रियों को बेहत्तर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिये विभागीय अधिकारियों को समुचित निर्देश दिये गये हैं।

टूटी या तोड़ दी गई आप - भाजपाई बने दीपक बाली को सीएम धामी ने बताया राष्ट्रवादी

फ़िरोज़ गाँधी की रिपोर्ट
न्यूज़ वायरस नेटवर्क

आम आदमी पार्टी उत्तराखंड को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है... उत्तराखंड आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक बाली ने भाजपा ज्वाइन कर ली है... इसके पहले बड़े ही नाटकीय ढंग से चौंकाते हुए सोमवार देर रात ही बाली ने आप से इस्तीफा दिया था. सीएम पुष्कर सिंह धामी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने दीपक बाली को भाजपा का पटका पहनाकर उन्हें सदस्यता ग्रहण करवाई. इसके बाद सीएम धामी और मदन कौशिक ने दीपक बाली को मिठाई खिलाकर उनका पार्टी में स्वागत किया...

अब सियासी हलके में ये अफवाह भी ज़ोर पकड़ने लगी है कि प्रदेश में बड़े जोर शोर से आगाज़ करने वाली आप को अचानक ये क्या हो गया है जहाँ उसके सभी दिग्गज एक एक कर साथ छोड़ रहे हैं। आपको याद दिला दें कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड को एक महीने के अंदर दूसरा बड़ा झटका लगा है. 24 मई को आम आदमी पार्टी से विधानसभा चुनाव 2022 में सीएम फेस रहे अजय कोठियाल ने भाजपा का दामन थामा था. तो अब आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बाली ने आप का दामन छोड़ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है. भाजपा प्रदेश मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद दीपक बाली ने अपने समर्थकों के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की...

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आम आदमी पार्टी प्रदेश से साफ हो चुकी है। पहले कर्नल (रिटा.) श्री अजय कोठियाल ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की और अब दीपक बाली भाजपा में शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड के अलावा हिमाचल प्रदेश, गुजरात एवं अन्य राज्यों से भी आम आदमी पार्टी का सफाया हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आठ वर्षों के कार्यकाल में देश में एक नई कार्य संस्कृति आई है। उनकी कार्यशैली से दुनिया में भारत का मान-सम्मान बढ़ा है। देश में भारतीय जनता पार्टी सशक्त होकर उभरी है। अन्य राजनीतिक दलों के लोग भाजपा की अच्छी नीतियों के कारण पार्टी में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि दीपक बाली की विचारधारा में हमेशा से राष्ट्रवाद था। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश के अध्यक्ष मदन कौशिक, महामंत्री कुलदीप कुमार, सुरेश भट्ट

देहरादून स्मार्ट सिटी लि0 के सिटी लेवल एजवाइजरी फोरम ने किया गुवाहाटी का दौरा

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून स्मार्ट सिटी लि0 के सिटी लेवल एजवाइजरी फोरम के सदस्यों एवं स्मार्ट सिटी के अधिकारियों ने गुवाहाटी स्मार्ट सिटी लि0, असम का दौरा किया और इस दौरे में कई अहम लोकेशन पर जाकर उनके ककरयों को देखा और समझा है। आपको बता दें कि इस डेलिगेशन में कई जन प्रतिनिधी एवं अधिकारी उपस्थित रहें। इनमे शामिल रहे सुनील उनियाल, गामा, माननीय मेयर, नगर निगम देहरादून , खजान दास, माननीय विधायक, राजपुर रोड, देहरादून , सविता कपूर, माननीय विधायक, कैण्ट, देहरादून , लोकेश ओहरी, स्वतन्त्र निर्देशक, देहरदून स्मार्ट सिटी लि0 जगमोहन सिंह चौहान, सहायक महाप्रबन्धक (सिविल), देहरादून स्मार्ट सिटी लि0 , कृष्ण पल्लव चमोला, सहायक महाप्रबन्धक (वाटर वकर्स), देहरादून स्मार्ट सिटी लि0 , प्रेरणा ध्यानी, जन सम्पर्क अधिकारी, देहरादून स्मार्ट सिटी लि0 गुवाहाटी स्मार्ट सिटी के दौरे के दौरान प्रतिनिधियों द्वारा गुवाहाटी स्मार्ट सिटी के अन्तर्गत किये जा रहे कार्यो के विषय में अध्यवधिक जानकारी प्राप्त कर गुवाहाटी स्मार्ट सिटी के परियोजना प्रबन्धक द्वारा किये जा रहे कार्यो का विस्तृत प्रस्तुतिकरण किया गया एवं देहरादून स्मार्ट सिटी लि0 के अधिकारियों द्वारा भी गुवाहाटी स्मार्ट सिटी के अधिकारियों के साथ देहरादून स्मार्ट सिटी के अन्तर्गत किये जा रहे कार्यो के विषय में जानकारी साझा की गई । गुवाहाटी स्मार्ट सिटी के अन्तर्गत प्रस्तावित निम्न मुख्य कार्य है।

- ब्रह्मपुत्र रीवर बैंक डेवलेपमेन्ट परियोजना,
- प्रक्यूरमेन्ट ऑफ 200 इलेक्ट्रिक बस परियोजना
- प्रक्यूरमेन्ट ऑफ 100 सी0एन0जी0 बस परियोजना
- स्मार्ट वॉटर ए0टी0एम0 परियोजना
- स्मार्ट टॉयलेट परियोजना
- व्यूटिफिकेशन ऑफ मार्केट एरिया अदि

प्रस्तुतिकरण के बाद देहरादून स्मार्ट सिटी के सिटी लेवल एजवाइजरी फोरम के सदस्यों एवं स्मार्ट सिटी के अधिकारियों द्वारा गुवाहाटी स्मार्ट सिटी द्वारा किये जा रहे कार्यो का स्थलीय निरीक्षण किया गया जिसमें मुख्य रूप से उमानन्द मन्दिर परिसर में मार्ग जिर्णोद्धार कार्य एवं शहर में ड्रेनेज हेतु बनाई जा रही नालिया एवं अन्य कार्य शमिल है। स्थलीय निरीक्षण के दौरान देहरादून स्मार्ट सिटी से गये प्रतिनिधियां द्वारा गुवाहाटी स्मार्ट सिटी अधिकारियों से कार्यो को बेहतर रूप से क्रियान्वयन हेतु विचार विमर्श किया गया।

संपादकीय

भारत की दो टूक

कोरोना महामारी, रूस-यूक्रेन युद्ध और अन्य कारणों से दुनियाभर में कई वस्तुओं के दामों में भारी वृद्धि हुई है. इसका सबसे अधिक असर खाद्य पदार्थों पर पड़ा है तथा विकासशील व अविकसित देश व्यापक रूप से प्रभावित हुए हैं. इस संकट से उबरने में अग्रणी भूमिका निभाने की जगह धनी देश अन्य देशों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं. भारत ने इस रवैये पर विश्व व्यापार संगठन, विशेष रूप से विकासित देशों को आड़े हाथों लिया है. संगठन के 12वें मंत्री-स्तरीय सम्मेलन में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय को महामारी और खाद्य संकट से उबरने के लिए अल्प विकसित देशों की मदद करनी चाहिए. उन्होंने उचित ही रेखांकित किया है कि महामारी ने 'एक विश्व, एक स्वास्थ्य' के महत्व को फिर से स्थापित किया है. भारत ने वैक्सीन और अन्य वस्तुओं की आपूर्ति में बढ़-चढ़कर योगदान किया है. लेकिन एक महत्वपूर्ण वैश्विक संस्था के रूप में विश्व व्यापार संगठन और धनी देशों ने अपेक्षित भूमिका नहीं निभायी. अविकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को आपूर्ति श्रृंखला में अवरोध का भी सामना करना पड़ रहा है. आगामी महीनों में खाद्य संकट और मुद्रास्फीति का क्या स्वरूप होगा, इसका अनुमान लगाना कठिन है. ऐसे में धनी देशों को महामारी के समय का व्यवहार नहीं करना चाहिए और वैश्विक स्तर पर स्थिति को बेहतर करने के लिए आगे आना चाहिए. गोयल ने तो यहां तक कह दिया कि महामारी के दौरान समय रहते समुचित पहल नहीं कर पाने के लिए हमें अपना सिर शर्म से झुका लेना चाहिए. खाद्य आपूर्ति के मामले में भी अगर ऐसा किया गया, तो करोड़ों लोगों का जीना मुहाल हो जायेगा. बढ़ती कीमतों का बोझ गरीब समुदायों और गरीब देशों को अस्थिर बाजार का गुलाम बना देगा. जैसा कि वाणिज्य मंत्री ने कहा है, देशों को अपनी खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए भी ठोस इंतजाम करना है. हमारे देश में दो साल से अधिक समय से 80 करोड़ लोगों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चल रही है, जो सितंबर तक जारी रहेगी. उसके बाद भी अनेक वर्गों के लिए ऐसी योजनाओं की आवश्यकता पड़ सकती है. राशन कार्ड वाले लोगों के लिए सस्ती दरों पर खाद्य पदार्थ मुहैया कराने की योजनाएं पहले से ही हैं. ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि हम खाद्यान्न का समुचित भंडारण करें. जलवायु परिवर्तन से खेती भी प्रभावित हो रही है. ऐसे में भंडारण के साथ-साथ पैदावार बढ़ाने के लिए उपाय करना भी जरूरी है. धनी देश इन पहलुओं को अनदेखा कर भारत समेत विकासशील देशों पर अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन कर अधिक अनुदान देने का आरोप लगाते रहे हैं. साथ ही, वे खाद्यान्न निर्यात के लिए भी दबाव बनाते हैं. गोयल ने साफ-साफ कहा है कि विकसित देश असल में अपने किसानों को अधिक अनुदान देते हैं. आशा है कि विकसित देश इन बातों का संज्ञान लेंगे.

ढूंढ रहे थे अंजलि को हाँथ लगा हकमुद्दीन

लड़की के नाम पर हकमुद्दीन करता था होटल बुकिंग का फर्जीवाड़ा -चमोली पुलिस ने धरा

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

चारधाम यात्रा के दौरान साइबर ठगों द्वारा फर्जी साइट तैयार कर ऑनलाइन होटल बुकिंग के नाम पर आम जनता से फोन व अन्य सोशल साईट्स के माध्यम से सम्पर्क कर लाखों रुपये की ठगी की जा रही है। इसी तरह का एक मामला 26 मई को बद्रीनाथ कोतवाली में सामने आयी जहाँ एक शिकायतकर्ता मोहिन्दर सिंह शिकायत दर्ज़ कराई कि 18 मई 2022 को उनके द्वारा 26 मई से 28 मई के लिए श्री बद्रीनाथ में ऑनलाइन होटल बुकिंग की गयी, जिसमें उनके साथ फ्रॉड किया गया है । उनके द्वारा 2800 रुपये अकाउंट नंबर 50100512594972 एचडीएफसी बैंक जो अंजलि के नाम से है, 2000 व 1200 रुपये क्यूआर कोड के माध्यम से होटल द्वारिकेश में कमरे की बुकिंग हेतु भेजे गए।

जिसके बाद उनके साथ कुल 6000/- रुपये का फ्रॉड हो गया, जिस पर कोतवाली श्री बद्रीनाथ पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। देशभर में श्रद्धालुओं के साथ घटित हो रही हेलीकॉप्टर बुकिंग फ्रॉड के बाद होटल बुकिंग फ्रॉड की घटना की गम्भीरता का स्वयं संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक जनपद चमोली श्वेता चौबे ने फ्रॉड करने वाले शातिर अपराधी की शीघ्र गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम गठित की। संयुक्त टीम एवं एसओजी व थाना गोपेश्वर में नियुक्त वरिष्ठ उपनिरीक्षक संजीव चौहान को इस मामले के खुलासे का ज़िम्मा सौंपा गया।

वरिष्ठ उपनिरीक्षक संजीव चौहान के नेतृत्व में एसओजी टीम ने सर्विलांस शाखा एवं तकनीकी सहायता से फोन कॉल्स एवं लोकेशन के आधार पर अभियुक्त का सुराग राजस्थान के भरतपुर में पाया। पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे ने तेज़ी दिखाती हुए इस बड़े मामले का जल्द से जल्द खुलासा करने के लिए सभी पुख्ता जानकारी मिलने के बाद गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम को राजस्थान रवाना किया।

साइबर अपराध तकनीकी यूनिट भरतपुर की सहायता एवं मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त को भरतपुर से गिरफ्तार किया गया। नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम हकमुद्दीन जिला भरतपुर राजस्थान बताया और जिसकी उम्र 22 वर्ष बताई जा रही है। अभियुक्त की तलाशी में एक मोबाइल व एक आधार कार्ड मिला जिसमें 8950661216 सिम था। पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर अभियुक्त के द्वारा बताया गया कि सिम एवं मोबाइल फोन का प्रयोग उसने Airtel Payment Bank का खाता खोलने में किया है, जिसका मैं धोखाधड़ी के पैसे निकालने में प्रयोग करता था। 18 मई कोउसने ही बद्रीनाथ में होटल द्वारिकेश की फर्जी बुकिंग की थी व एयरटेल पैमेंट बैंक से पैसे निकाल लिए थे जिसके बाद मोबाइल व सिम फेंक दिया था।

अभियुक्त से पूछताछ में अहम सुराग प्रकाश में आये हैं। इसके द्वारा अंजली नाम के खाता संख्या 50100512594972 में मई माह में 27 लाख से अधिक की धोखाधड़ी देश के विभिन्न हिस्सों से ऑनलाइन होटल बुकिंग फ्रॉड फर्जी आईडी के सिम के माध्यम से किया गया। अभियुक्त द्वारा लॉकडाउन के दौरान ओएलएक्स, किताबों व शराब की होम डिलीवरी के नाम पर भी फ्रॉड किया गया। चमोली पुलिस को चारधाम यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले होटलों व धर्मशालाओं में अंजली नाम से कई लोगों के साथ ठगी की शिकायतें पूर्व में प्राप्त हो चुकी है। जिसमें निकट भविष्य में गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी की जाएगी।

मेयर की फेसबुक अकाउंट को हैक करने वाला पुलिस के शिकंजे में

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

बीते दिनों नगर निगम ऋषिकेश की मेयर अनीता ममगई के पीआरओ ने कोतवाली ऋषिकेश में शिकायत दर्ज़ कराई थी कि महापौर ऋषिकेश के नाम पर फेसबुक अकाउंट है। कुछ समय पूर्व इसी अकाउंट पर अनीता ममगाईं नाम से एक फेसबुक पेज बनाया गया था जिसे वेरीफाइड भी कराया गया था। दिनांक 21 अप्रैल 2022 को इस पेज पर एक मैसेज प्राप्त हुआ कि जिस पर your full control of anita mamgain was removed लिखा हुआ था। जिसके पश्चात हमारे द्वारा अपने आईटी सेल में शिकायत दर्ज की गई।

शिकायत में कहा गया था कि बीते 26 अप्रैल 2022 को उस पेज पर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा गेम व अन्य पोस्ट अपलोड की जा रही है व वर्ष 2022 की बाकी सारी पोस्ट पेज से हटा दी गई है। जिससे यह प्रतीत होता है कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा इस पेज से छेड़छाड़ की जा रही है , पेज के ठीक होने तक यदि कोई भ्रामक या गलत पोस्ट अपलोड की जाती है तो पोस्ट की जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। इसलिए पेज से छेड़छाड़ करने वाले अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाए। इस शिकायत के बाद प्रभारी निरीक्षक कोतवाली ऋषिकेश ने तेज़ी से कार्यवाही करते हुए कोतवाली हाजा पर मुकदमा दर्ज़ कर जांच पड़ताल शुरू की।

एसटीएफ एवं साइबर क्राइम थाना से तकनीकी सहायता प्राप्त कर जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि अभियुक्त विपिन कुकरेती , थाना रायवाला जनपद देहरादून के द्वारा अपने MI मोबाइल जिसके अंदर जिओ कंपनी के 2 सिम है का प्रयोग करते हुए उपरोक्त फेसबुक अकाउंट के साथ छेड़छाड़ कर अनावश्यक रूप से पोस्ट अपलोड की गई है। जिसके बाद 13 जून 2022 को अभियुक्त के विरुद्ध वैधानिक कानूनी कार्रवाई करते हुए अभियुक्त के कब्जे से मोबाइल फोन एवं जिओ कंपनी के 2 सिम को कब्जे में लेकर सील किया गया है।

पूछताछ करने पर अभियुक्त के द्वारा बताया गया कि कुछ समय पहले तक वो ही महापौर नगर निगम ऋषिकेश के फेसबुक पेज को संचालित करता था परंतु बाद में मुझे इस कार्य से हटा दिया गया जिसके कारण उसने इस घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल राहत की खबर है कि समय रहते तेज़ी से कार्यवाही करते हुए शातिर को पकड़ लिया गया है जिसके बाद नगर निगम की महापौर ने राहत की सांस ली है।

श्रीगुडीया श्री जग्गनाथ भगवान का मंगलस्नान सम्पन्न , 1 जुलाई को रथ यात्रा

हर वर्ष की तरह देहरादून दीपलोक कालौनी के प्रसिद् राम मंदिर में भगवान श्री जगन्नाथ स्वामी मां सुभद्रा व बलभद्र भगवान की यात्रा की तैयारियां कलश यात्रा व तत्पश्चात मंदिर में विधिवत पूजन अर्चना के साथ भगवान जगन्नाथ मां सुभद्रा व बलभद्र भगवान का मंत्रोच्चार के साथ मंगलस्नान किया गया। मुख्य यजमान के रूप में प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने पंडित सतपति जी,मंदिर समिति के अध्यक्ष प्रमोद कुमार गुप्ता ,पृथ्वीनाथ भगवान मंदिर के अध्यक्ष संजय गर्ग, सुनील अग्रवाल, सुनील बांगा ,व अन्य श्रद्धालुओं के साथ भगवान को स्नान करवाया । इस अवसर पर सूर्यकांत धस्माना ने मंदिर समिति के पदाधिकारियों, पंडित सतपति सभी उपस्थित श्रद्धालुओं व देहरादून वासियों को भगवान के उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई देते हुए भगवान की शोभायात्रा को ऐतिहासिक बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यह भगवान श्री जगन्नाथ जी की कृपा ही है कि वैश्विक महामारी कोरोना के प्रकोप के बाद हम एक बार फिर भगवान की पूजा अर्चना व उनकी यात्रा की तैयारी कर रहे हैं।इस अवसर पर पंडित सुभाष चंद्र सतपति,प्रमोद गुप्ता, सुनील अग्रवाल ,जे एस चुग,अनिल बांगा,संजय गर्ग, एल डी आहूजा,आर के गुप्ता,नारायण दास,संगीता गुप्ता पार्षद,बिना बिष्ट, बैनी माधव त्रिपाठी,मीनाक्षी गोदियाल, के एल सचदेवा ,पंडित पुरषोत्तम डिमरी जी समेत बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित रहे।

लापरवाही छोड़ सप्लाई चेन व्यवस्थित रखें तेल कंपनियां : डॉ आर राजेश कुमार , DM देहरादून

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून में पेट्रोल , डीजल की किल्लत को लेकर उड़ाई जा रही भ्रामक अफवाह पर डीएम देहरादून ने सख्त कदम उठाने का इशारा दे दिया है। झूठी अफवाह उड़ाने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने के साथ साथ उन्होंने तेल कंपनियों को भी कड़े निर्देश दिए हैं

मंगलवार को एक अहम बैठक बुलाते हुये डीएम डॉ आर राजेश कुमार ने एचपीसीएल, इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम के अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने तेल कंपनियों के प्रतिनिधियों को जनपद में तेल आपूर्ति को गंभीरता से लेने तथा डिस्ट्रिक कार्डिनटर एचपीसीएल, इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड , भारत पेट्रोलियम को प्रत्येक रिटेल आउटलैट के स्टॉक/उठान/वितरण की दैनिक सूचना जिला पूर्ति कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

बैठक में जिलाधिकारी डॉ राजेश कुमार ने एचपीसीएल के डीजीएम रिटेल से एचपीसीएल के कुछ पेट्रोल पम्प पर सोमवार को हुई तेल किल्लत का कारण पूछा जिस पर उन्होंने बताया कि डिपो से पूर्ण सप्लाई वाहन समय से न पहुंच पाने के कारण यह स्थिति बनी। जिस पर जिलाधिकारी ने सभी तेल कम्पनियों के पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि भविष्य में इस प्रकार की लापरवाही न हो साथ ही सप्लाई चेन व्यवस्थित रखें साथ ही पेट्रोल की किल्लत संबंधी भ्रामक सूचना देने वाले आउटलैट पर अपने स्तर से कार्यवाही करें। भविष्य में इस प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

जिलाधिकारी ने बताया कि पेट्रोल/डीजल की किल्लत को लेकर आम लोगों के बीच अफवाह फैलाई जा रही है कि जिले में पेट्रोल/डीजल की किल्लत बनी है। जबकि जिला पूर्ति अधिकारी एवं स्थानीय प्रशासन से जांच करने पर पाया गया कि इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड तथा भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड के पम्पों पर डीजल/पेट्रोल की आपूर्ति सुचारू रूप से संचालित की जा रही है डीजल/पेट्रोल का स्टॉक पर्याप्त है।

इस सम्बन्ध में जिला पूर्ति अधिकारी एवं तेल कम्पनी के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई है बैठक में अधिकारियों ने बताया कि मांग के अनुसार पर्याप्त आपूर्ति की जा रही है किन्तु HPCL के कुछ पम्पों में तेल की कमी होने से अन्य पम्पों पर दबाव अधिक बड़ा है जिस सम्बन्ध में HPCL के अधिकारियों द्वारा शीघ्र ही स्थिति को सामान्य किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।इस

अफवाह को गंभीरता से लेते हुए डीएम देहरादून ने सभी उप जिलाधिकारियों, जिला पूर्ति अधिकारी एवं तेल कम्पनी के अधिकारियों को निर्देश दिये गये है कि भ्रामक सूचना अथवा अफवाह फैलाने वाले के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाए।

सरकार का बजट सिर्फ शिगूफा : जोत सिंह बिष्ट, प्रदेश संगठन समन्वय, आप

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

आम आदमी पार्टी के प्रदेश संगठन समन्वय जोत सिंह बिष्ट ने प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए गए बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ,सरकार ने जो बजट पेश किया है इसका सिर्फ आकार बढ़ाया गया है और गरीबों को इस बजट में कोई तवज्जो नहीं दी गई है।जोत सिंह बिष्ट ने आगे कहा कि राज्य के बेरोजगारों के लिए इस बजट में किसी तरह की कोई राहत नहीं दिखाई दे रही है ,साथ ही महिलाओं को भी इस बजट में तवज्जो नहीं दिया गया है।उन्होंने कहा कि इस बजट में एक बार फिर से सरकार द्वारा केंद्र से कर्ज लिया गया है जो लगातार प्रदेश पर कर्जा बढ़ रहा है।जोत सिंह बिष्ट ने कहा कि इस बजट को लेकर ऐसा प्रतीत हो रहा है आने वाले समय में यह बजट प्रत्येक व्यक्ति के लिए 85 हज़ार का बोझ लेकर आएगा, और राज्य पर 98 हज़ार करोड का कर्जा चढ़ जायेगा, उन्होंने कहा कि यह बजट पूरी तरह गरीब विरोधी बजट है।उन्होंने कहा कि यह बजट निराशा

वादी बजट है, और सरकार विकास के बजाय दूसरे दलों में तोड़फोड़ को लेकर पैसा खर्च कर रही है और साथ ही चुनाव प्रबंधन पर व्यय कर रही है।

कांग्रेस मीडिया प्रभारी राजीव महर्षि ने धामी सरकार के वजट को बताया शब्दजाल

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

उत्तराखंड प्रदेश कॉंग्रेस के मीडिया प्रभारी राजीव महर्षि ने धामी सरकार द्वारा मंगलवार को विधानसभा में पेश किये गए बजट को महज शब्दजाल करार दिया है। उन्होने कहा कि जिन योजनाओं का बजट में प्रावधान किया गया है वे सब या तो केन्द्र पोशित हैं या फिर बाह्य सहायतित हैं। धामी सरकार का इसमें सिर्फ गाल बजाने का योगदान है। रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, पलायन की रोकथाम जैसे मद्दों को केवल औपचारिक रूप से बजट में शामिल किया गया है।

महर्षि ने धामी सरकार के इस बजट को आम जनता के साथ छलावा करार देते हुए कहा कि इस बजट से लोगों को सिर्फ निराशा ही हाथ लगी है। इसमें आकडों की बाजीगरी के अलावा कुछ नहीं है। कॉंग्रेस मीडिया प्रभारी ने कहा कि गैरसैंण के विकास के लिए बजट की व्यवस्था न कर सरकार का दोहरा चरित्र उजागर हो गया है, जबकि यह सरकार ग्रीष्मकालीन राजधानी का राग अलापने में नहीं

थकती। उन्होंने कहा कि 65571.49 करोड़ का बजट दिखने में बेशक लोकलुभावन है लेकिन वस्तुत इसमें न तो राहत की उम्मीद जगती है और न विकास की कोई दिशा ही है। उन्होंने कहा कि सरकार का यह दावा सत्य से परे है कि प्रदेश के विकास के लिए बजट में हर सेक्टर और वर्ग पर फोकस किया गया है।काग्रेस मीडिया प्रभारी ने कहा कि प्रदेश के गढ़वाल व कुमाऊं मंडल के विभिन्न जिलों से पलायन पर प्रभावी प्रहार के लिए ठोस रणनीति बनाने की बात जरूर बजट में की गई है लेकिन पलायन रोकथाम योजना के लिए मात्र 25 करोड़ रखे गए हैं। इसी तरह सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए मात्र 44.78 करोड़ और मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना के लिए 20 करोड़ का प्रावधान है। जबकि सीमांत क्षेत्र हमारी द्वितीय रक्षा पनक्ति है। इससे सरकार की गम्भीरता साफ झलकती है।

सदन में 'अपात्र को ना और पात्र को हां' मुहिम का उठा मुद्दा : मंत्री रेखा आर्या ने साधा विपक्ष पर निशाना

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

विधानसभा के बजट सत्र के दौरान खाद्य मंत्री रेखा आर्या द्वारा चलाई जा रही ₹अपात्र को ना व पात्र को हां₹ मुहिम के तहत नियम 58 के तहत चर्चा की गई । नियम 58 के अंतर्गत विपक्षी विधायको द्वारा कई सवालों को विधानसभा के पटल पर उठाया गया । मंत्री रेखा आर्या ने विपक्षी विधायकों के सवालों की जानकारी देते हुए बताया कि विपक्षी विधायक जिस विषय को सदन के पटल पर उठा रहे हैं जिसमे यह कहा जा रहा है कि जिस परिवार के सदस्यों की मासिक आय 15 हजार से ज्यादा है ,जिनके पास चार पहिया वाहन या जिन परिवारों के पास दो हेक्टेयर सिंचित भूमि है ऐसे परिवार नए नियमो के तहत अपात्र होंगे साथ ही इसका आर्थिक सर्वेक्षण कराया जाए। मंत्री आर्या ने बताया कि नए नियम के आधार पर आम जनता के बीच किसी भी प्रकार की भ्रम की स्थिति नही है । ₹अपात्र को ना व पात्र को हां₹अभियान बीते 5 मई को एक अपील के रूप में शुरू की गई थी जिसका की पूरे प्रदेश में एक सकारात्मक परिणाम देखने को मिला । यही कारण भी है कि अभी तक पूरे प्रदेश में अंत्योदय अन्न योजना के 5060,प्राथमिक परिबार के 39,733 एवम राज्य खाद्य योजना के 15,330 सहित कुल 60,515 राशन कार्ड अबतक सरेंडर हो चुके हैं । मंत्री रेखा आर्या बताया गया कि 13जून 2022 की स्थिति के अनुसार समस्त श्रेणियों में समर्पित किये गए कुल 2 लाख 47 हजार 697 अपात्र लाभार्थियों को योजना से बाहर करते हुए इसके स्थान पर पात्र लाभार्थियों को इस योजना में शामिल किया जाएगा ।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत पात्रता के यह हैं मानक

1: ऐसा परिवार जिसका संचालन मुखिया

के तौर पर विधवा महिला या अकेली महिला करती हो तथा परिवार की कुल मासिक आय 15 हजार से कम हो ।2: ऐसा परिवार जिसका संचालन मुखिया के तौर पर असाध्य रोगों (कुष्ठ/एच .आई.बी.) से पीड़ित अथवा विकलांगता /60 वर्ष से अधिक आयु वाला बुजुर्ग व्यक्ति करता हो तथा परिवार की कुल मासिक आय 15 हजार से कम हो ।3:आदिम आदिवासी तथा सीमांत क्षेत्रो में निवासरत आदिवासी परिवार ।4: ऐसा परिवार जिनके पास राजस्व अभिलेखों में दर्ज सिंचित भूमि का कुल क्षेत्रफल 2 हेक्टेयर से कम हो अथवा 1 हेक्टेयर सिंचित भूमि अथवा 2 हेक्टेयर असिंचित से कम हो अथवा कुल क्षेत्रफल 4 हेक्टेयर असिंचित भूमि से कम हो ।5: शहरी क्षेत्रो में झुग्गी-झोपड़ी में उत्तराखंड राज्य की स्थापना के पूर्व से निवासरत परिवार ।6: विधवा आश्रम ,बाल -महिला सुधार गृह, भिक्षुक गृह, कुष्ठ आश्रम,अनाथ आश्रम ,मानसिक रोग आश्रम विकलांग आश्रम एवम वर्धाश्रम में निवासरत व्यक्ति ।7:राज्य खाद्य योजना के अंतर्गत शासनादेशानुसार पांच लाख वार्षिक आय से कम आय वाले परिवारों को सम्मलित किया गया।

दैनिक
न्यूज वायरस
न्यूज़ वायरस नेटवर्क प्रा. लिमिटेड, मेरठ के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक मौ. सलीम सैफी द्वारा विश्वनाथ प्रिंटर्स, अजबपुर कलां, देहरादून से मुद्रित एवं 48/3 बलबीर रोड, डालनवाला, देहरादून (उत्तराखंड) से प्रकाशित।
सम्पादक :
मौ. सलीम सैफी
कार्यकारी सम्पादक
आशीष तिवारी
दूरभाष : 0135-2672002
email-dainiknewsvirus@gmail.com
RNI No.- UTTHIN/2012/44094
वाद-विवाद का न्याय क्षेत्र देहरादून न्यायालय मान्य होगा